International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 11-12-2020; Accepted: 26-12-2020; Published: 16-01-2021
www.hindijournal.com
Volume 7; Issue 1; 2021; Page No. 13-15

गैर सरकारी संगठनों का बढ़ता व्यवसायीकरण और 'नरक मसीहा' उपन्यास

प्रदीप कुमार
पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
समाज के विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न उद्देश्यों को लेकर ये अलाभकारी संगठन सामाजिक कार्यों को गति देते हैं। इन संगठनों को समाज के विकास के लिए विभिन्न माध्यमों से वित्त प्राप्त होता है जिसका प्रयोग करके ये सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है। ये समाज कल्याण के मार्ग को भूलकर अपना हित साधने में लग गए हैं। कुछ संगठन बाहरी एजेंसियों के प्रभाव से राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एफ.सी.आर.ए. एक्ट के तहत कार्य न करने वाले बहुत सारे संगठनों पर प्रतिबन्ध भी लगाया है। 'नरक मसीहा' उपन्यास गैर सरकारी संगठनों के बढ़ते व्यवसायीकरण की पड़ताल करता है। इस उपन्यास में विभिन्न कार्य करने वाले एन.जी.ओ. का मकड़जाल है जो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एन.जी.ओ. चलाते हैं।

मूलशब्द: एन.जी.ओ., समाज, सरकार, आदिवासी, एफ.सी.आर.ए., जन आंदोलन, विचारधारा, राजनीति, मीडिया

प्रस्तावना

भगवानदास मोरवाल द्वारा रचित उपन्यास 'नरक मसीहा' एन.जी.ओ. पर आधारित उपन्यास है। एन.जी.ओ. यानि गैर सरकारी संस्थान समाज कल्याण के लिए खोले गए संस्थान होते हैं। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में भी तमाम धार्मिक एवं सामाजिक संगठन कार्य कर रहे थे। सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथा आदि को दूर करने के लिए इन संगठनों ने काम किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज आदि संगठनों ने समाज में शिक्षा के लिए एवं सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए बहुत काम किया।

गैर सरकारी संगठनों का निर्माण एवं विकास भी समाज कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया। विश्व बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन की परिभाषा है–''ऐसे निजी संगठन जो कुछ इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनसे किसी की परेशानी दूर हो, गरीबों के हितों को बढ़ावा मिले, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता हो, मूलभूत सामाजिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हो या सामाजिक विकास का जिम्मा उठाया जाता हो।''[1]

ग्रेंगैड के अनुसार –''स्वैच्छिक संगठन वे होते हैं जो कि वैधानिक रूप से पंजीकृत हो, उनका एक प्रशासनिक ढांचा हो, उनके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो और उसके सदस्य बाहरी दबावों से मुक्त तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए निर्णय एवं कार्य करते हैं।[2]

इन संगठनों का उद्देश्य और प्रकृति अलाभकारी होती है। लेकिन आज इनमें से बहुत सारे संगठनों का रूप विकृत हो गया है। आज एन.जी.ओ. खोलने का उद्देश्य समाज कल्याण नहीं बल्कि व्यवसाय बनता जा रहा है। व्यवसाय और मुनाफे को ध्यान में रखकर एन.जी.ओ. खोले जा रहे हैं। 'नरक मसीहा' उपन्यास में एन.जी.ओ. के इसी विकृत होते जा रहे रूप की पड़ताल की है।

गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत सामाजिक बदलाव के लिए की गई थी। ये संगठन समाज में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। जैसे– 'ग्रीनपीस फाऊंडेशन' पर्यावरण संरक्षण, 'बचपन बचाओ' बाल–श्रम उन्मूलन एवं बाल–शिक्षा के लिए, 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' देश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य करता है। इसी प्रकार तमाम एन.जी.ओ. महिला अधिकारों, मानवाधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, हाशिये के समाज आदि के लिए कार्य कर रहे हैं। एन.जी.ओ. सरकारी योजनाओं को भी उन तबकों तक पहुंचने का कार्य करते हैं, जहां ये योजनाएँ पहुँच नहीं पाती हैं।

जिन उद्देश्यों को लेकर एन.जी.ओ. चले थे, अब वे अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं। 'नरक मसीहा' उपन्यास के कथ्य की बात करें तो इसमें विभिन्न गैर सरकारी संगठन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं। इनमें 'राहत फाउंडेशन' की अध्यक्ष अमीना खान, 'अखिल भारतीय अबला मंच' की अध्यक्ष सरला बजाज, 'डालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' की अध्यक्ष टीना डालमिया, 'डॉ. अम्बेडकर दलित महिला सभा' की अध्यक्ष सुमन भारती, 'बाल एवं महिला कल्याण परिषद' की अध्यक्ष बहन भाग्यवती हैं। लेकिन ये सभी अपने एन.जी.ओ. के माध्यम से गरीबों के कल्याण के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं। इनकी वास्तविकता दूसरी है।

महिला कल्याण परिषद् की अध्यक्ष बहन भाग्यवती अपने पूरे साल का कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करती हैं। ये महिला आरक्षण बिल के लिए रिजर्वेशन एक्सप्रेस, मानव श्रृंखला आदि अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाती हैं। वास्तविकता ये है महिला अधिकारों की बात करने वाले ये संगठन सरकार द्वारा दिये जाने वाले ग्रांट को अपनी मौज मस्ती में प्रयोग करते हैं। 'नरक मसीहा' में भी ये संगठन इंडिया गेट पर केवल मौज मस्ती एवं सुर्खियां बटोरने के लिए जाते हैं। अबला मंच की अध्यक्ष सरला बजाज कहती हैं–''मैं तो फोटू खिंचवाने पूरी फैमिली को लाऊँगी।''[3]

गैर सरकारी संगठनों को एफ.सी.आर.ए. के नियम के तहत विदेशी अनुदान प्राप्त होता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने हजारों एन.जी.ओ. के लाइसेंस रद्द किये हैं। इन पर विदेशी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। भारत सरकार ने एफ.सी.आर.ए. के नियमों में भी बदलाव किया है। एफ.सी.आर.ए. 2010 के नियम के तहत अब साल के खत्म होने के बाद सभी संस्थाओं को ये जानकारी देनी होगी कि उन्हें फण्ड कहाँ से मिला और कितना मिला।

विदेशों से मिले अनुदान को सामाजिक विकास एवं समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये संगठन विदेशी फंडिंग एजेंसियों से सांठ–गांठ कर लेते हैं। ये इन

एजेंसियों की कठपुतली बनकर उन्हीं के एजेंडे पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये एन.जी.ओ. विकास से संबंधित परियोजनाओं में भी बाधा बन रहे हैं। मीडिया में लीक हुई आइ.बी. ;प्ठद्ध की एक रिपोर्ट के अनुसार ये संगठन भारत की जी.डी.पी. ;ळक्व्द्ध का 2 से 3 फीसदी तक नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि विकास से संबंधित योजनाओं में बाधा पहुँचा रहे हैं। सरकार ने अमेरिकी एन.जी.ओ फोर्ड फाऊंडेशन को निर्देश दिया है कि गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी भी एन.जी.ओ. को अनुदार न दे। कुडनकुलम (तमिलनाडु) में एक एन.जी.ओ. ने परमाणु ऊर्जा प्लान्ट का विरोध किया था तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि अमेरिका से अनुदान प्राप्त एक एन.जी.ओ विकास के कार्य को रोक रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने ग्रीन पीस एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों को सीज करके उनसे अनुदान संबंधित रिपोर्ट मांगी है। जो एजेंसियां फंडिंग करती है, वे अपना एजेंडा भी सेट करती हैं तथा तमाम गैर सरकारी संगठन उनके ऐजेण्डे पर काम भी करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफेम, ओसाका फाउंडेश, नोराड, यूएसएड, प्लान इंटरनेशनल आदि विभिन्न देशों की फंडिंग ऐजेंसियां हैं। एक तरफ ये तो एन.जी.ओ. गरीबों के मसीहा बनते हैं तथा दूसरी ओर इन एजेंसियों के चक्कर काटते रहते हैं। 'नरक मसीहा' उपन्यास में कबीर कहता है–''अगर चक्कर ही काटने हैं तो विश्व बैंक में बैठे अपने देशी दलालों के काटो।''[4]

शुरुआती दौर में एन.जी.ओ. संचालक एवं उनके सदस्य समाज सेवा के लिए बहुत समर्पित थे। ये अपनी योजनाओं एवं प्रोजेक्टों के लिए बैठक अपने कार्यालय में करते थे, लेकिन अब इनकी मीटिंग कार्यालयों में नहीं बल्कि फाइव स्टार होटलों एवं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आदि स्थानों पर होती है। इनको जिन योजनाओं के लिए धन प्राप्त होता है, वे उसे उस योजना को पूरा करने के बजाय आपस में बांट लेते हैं। 'नरक मसीहा' में बहन भाग्यवती को 'यंग प्रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन' की ओर से ग्रामीण मुस्लिमों एवं दलित समुदायों के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट प्राप्त होता है। उसको वह सानिया पटेल एवं अमीना खान के एन.जी.ओ. को देती है एवं उसमें अपना हिस्सा तय करती है। उस अनुदान को एन.जी.ओ. संचालक आपस में बांट लेते हैं। बहन भाग्यवती कहती हैं–''...और पूरा शेयर मेरी जेब में थोड़े ही जाएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक के उन लोगों का भी शेयर होगा, जो हमें यह प्रोजेक्ट दिला रहे हैं।''[5]

एन.जी.ओ का पंजीकरण कई प्रकार से कराया जा सकता है, जिसमें भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 तथा कंपनी अधिनियम 1956 शामिल हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत कम्पनी को अपने मुनाफे में से दो प्रतिशत सामाजिक कल्याण के कार्य के लिए खर्च करना है। ऐसे में बहुत सारे पूंजीपति अपना एन.जी.ओ. खोल लेते हैं, ताकि उस पैसे को एन.जी.ओ. के माध्यम से बचाया जाए और कर मुक्त पैसों में बदला जाए। इसके साथ ही बहुत सारी कम्पनियाँ किसी एन.जी.ओ. के साथ गठजोड़ कर लेती हैं ताकि वे अपना उत्पाद को बेच सके। 'नरक मसीहा' उपन्यास में विभिन्न एन.जी.ओ. अपने उत्पाद को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। डॉ. अम्बेडकर दलित उद्धार सभा की अध्यक्ष सुमन भारती का एन.जी.ओ. मोमबत्ती बनाता है। वह चाहती है कि जंतर–मंतर और इंडिया गेट पर जो कैंडल मार्च होगा, उसके लिए मोमबतियाँ उसके ही एन.जी.ओ. से खरीदी जाए ''मैम मोमबत्ती तो मेरी एन.जी.ओ. भी बनाती है। अगर उचित समझो तो ऽऽऽ।''[6] इसके अलावा इस उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे ये एन.जी.ओ. गरीबों को पैसा कमाने का औजार बना दिया है। 'मनस्वी हस्तशिल्प' मेले में विभिन्न अंचल विशेष की हस्तशिल्प कलाओं के ये एन.जी.ओ. सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें विदेशों में बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं।

विचारधारा का अपना एक सिद्धान्त होता है। विचारधाराएँ चाहे गांधीवादी विचारधारा हो, अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे मार्क्सवादी विचारधारा चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा हो, सभी अपने सिद्धान्तों पर कार्य करती हैं। गांधी जी सर्वोदय पर जोर देते थे। वे कहते थे कि व्यक्ति का उत्थान होगा तभी उसके साथ समाज का उत्थान होगा। वे समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक के विकास की बात करते थे। इसी प्रकार सभी विचारधाराएं अपने सिद्धांतों के आधार पर समाज के उत्थान की बात करती हैं। गैर सरकारी संगठन आखिरी व्यक्ति तक के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं के लिए भी विभिन्न वैचारिक महापुरुषों की विचारधारा का बहुत महत्व होता है। लेकिन अब ये पक्ष धीरे–धीरे कमजोर होता जा रहा है। आज के दौर में एन.जी.ओ. के संस्थापकों के लिए विचारधारा का कोई महत्त्व नहीं रहा।

उपन्यास 'नरक मसीहा' में विभिन्न वैचारिक प्रतिबद्धता वाले एन. जी.ओ. हैं, लेकिन भीतर से ये सभी एक मंच पर खड़े दिखते हैं। सभी संगठन पूंजीवाद के समर्थन में दिखाई देते हैं। बहन भाग्यवती गांधीवादी विचारधारा की स्त्री हैं। लेकिन गांधी जी के मायने उनके लिए कार्यालय की शोभा बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी कार्यक्रम में गांधी जी के वाक्यों के दोहरा दिया जाता है। गंगाधर आचार्य कहते हैं ''वंदना जी गांधीवादी होने का अर्थ यह नहीं कि उसका जब चाहे, जहां चाहे छोंक लगा दो। जहां चाहो, जब चाहो पोस्टर की तरह चिपका दो, और जब जी चाहे फाड़कर कूड़ेदान में डाल दो।''[7]

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। मीडिया का दायित्व है कि समाज के हर पहलु को अपनी तटस्थता के साथ दिखाए। किसी भी स्वस्थ एवं सभ्य समाज में मीडिया की स्वतन्त्रता बहुत आवश्यक है। लेकिन आज के दौर में मीडिया पर पूंजीपतियों का अधिकार बढ़ रहा है। पूंजीपति वर्ग मीडिया को भी अपने अनुसार संचालित करने लगे हैं। एन.जी.ओ. संचालक भी स्वयं को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए मीडिया से सांठगांठ कर लेते हैं। ये चाहते हैं कि उनके एन.जी.ओ. मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करें ताकि देश–विदेश से भारी अनुदान मिल सके। उपन्यास में अखिल भारतीय अबला मंच की अध्यक्ष सरला बजाज टीना डालमिया से कहती हैं–''मैडम यही तो मौका है अपनी एन.जी.ओ. को मीडिया में सामने लाने का। देखना, पूरा देश देखेगा अपने एन.जी.ओ. के बैनर को।''[8] झूठी खबर एवं मक्कारी द्वारा ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं। अपने एन.जी.ओ. के लिए फंड हासिल करने के लिए मेवात में 'गर्ल्स चाइल्ड एजूकेशन और ट्रैफिकिंग' पर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए अमीना खान अपने एन.जी.ओ. के हवाले से झूठी रिपोर्ट अखकार में देती है कि मेवात में पन्द्रह हजार रुपये में लड़कियां बेची जा रही हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। सानिया पटेल के पूछने पर वह बताती है–''खबर को सेंशनल बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ता है....दरअसल इस अखबार की रिपोर्टर मेरी पुरानी दोस्त है, उसी ने प्लान की थी यह रिपोर्ट।''[9]

गैर सरकारी संगठन अलाभकारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। लेकिन धीरे–धीरे ये संगठन आर्थिक एवं राजनैतिक हस्तक्षेप करने लग गए हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के अपने एन.जी.ओ. हैं। ''नब्बे के दशक में राजीव गांधी एवं उसके बाद नरसिम्हा राव ने भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ ही एन.जी.ओ. को भी पूर्ण जगह दी। शुरू में ये संगठन सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने देश की आर्थिक नीतियों में भी दखलंदाजी शुरू कर दी। अब ये सीधे तौर पर राजनीति में उतर आये तथा ये सत्ता पर काबिज होने के लिए काम करने लगे।''[10]

भ्रष्टाचार के विरूद्ध दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन में बहुत

सारे एन.जी.ओ. के संचालकों ने भाग लिया। आज उनमें से बहुतों ने अपनी राजनैतिक पार्टियां बना ली हैं। ऐसा लगता है कि आंदोलन की आड़ में वे सियासी जमीन तलाश रहे थे।

अपने राजनैतिक वर्चस्व के लिए ये एन.जी.ओ. लोगों की भीड़ इकट्ठा करके सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। इन गैर सरकारी संगठनों ने जन–आंदोलनों को कमजोर किया है।

कुछ गैर सरकारी संगठन इन आंदोलनों में शामिल होकर इन्हें अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। 'नरक मसीहा' का कबीर आदिवासियों की जमीन की रक्षा के नाम पर जन–आंदोलन करता है। वह इस आंदोलन का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है। वह इस आंदोलन के सफल होने पर राजनेताओं की तरह सरकार पर दबाव बनाकर महत्त्वपूर्ण पद हासिल करना चाहता है। वह हजारों गरीब संघर्षशील भूखे–प्यारे, नंगे पांव छाले पड़े आदिवासियों और सत्याग्रहियों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है। वह कहता है –''मैं तो चाहता हूं कि आगरा, वरना ज्यादा से ज्यादा मथुरा पहुंचने से पहले कोई समझौता हो जाए। वैसे इस सत्याग्रह के पीछे मेरी मंशा सरकार को डराना भर है।'' [11]

गैर सरकारी संगठन समाज की भलाई के लिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों एवं परियोजनाओं पर काम करते हैं जैसे आदिवासियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए आदि। लेकिन इनमें से कई संगठन एफ.सी.आर.ए. के तहत फण्ड तो ले लेते हैं। लेकिन उसका प्रयोग अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में नहीं करते हैं। बल्कि अपने निजी हित साधने के लिए एन.जी.ओ. का प्रयोग करते हैं। 'नरक मसीहा' में आदिवासी बच्चों की देखभाल के नाम पर एन.जी.ओ. संचालक 'मारथा एक्का' नामक आदिवासी लड़की को नौकरानी के रूप में काम करवाती है। इसी तरह बुजुर्गों की देखभाल करने के नाम पर टीना डालमिया अपने एन.जी.ओ. के माध्यम से 'हारमनी फॉर गोल्डन फाउंडेशन' के तहत इंडिया गेट पर बुजुर्गों की मैराथन दौड़ करवाती है। वह केवल मीडिया में अपने एन.जी.ओ. को लाना चाहती है।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आज समाज के विकास के लिए सरकार के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों की जरूरत है। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर भी रहे हैं। सरकार द्वारा एवं समाज द्वारा ऐसे संगठनों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे संगठनों पर लगाम कसनी चाहिए, जो सामाजिक कल्याण के नाम पर समाज का पैसा लूट रहे हैं एवं विभिन्न एजेंडों को चला रहे हैं। 'नरक मसीहा' उपन्यास ऐसे ही गैर सरकारी संगठनों की पोल खोलता है।

संदर्भ सूचीं

1. https://www.google.co.in/amp/m.jagran.com/
2. राजपूत, उदय सिंह; आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर; संस्करण 2010; पृ. 49–50
3. मोरवाल, भगवानदास; नरक मसीहा, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली–110002; संस्करण 2015, पृ. 35
4. वही, पृ. 50
5. वही, पृ. 54
6. वही, पृ. 37
7. वही, पृ. 39
8. वही, पृ. 92
9. वही, पृ. 151
10. https://www.chauthiduniya.com/2014/07/videshi fundsanchalit, 09.06.2017
11. मोरवाल, भगवानदास; नरक मसीहा; राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, संस्करण 2015, पृ. 171